भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 246

<u>दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

प्रत्यक्ष निर्यात कार्ययोजना

246. श्री अतुल गर्गः
श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष निर्यात कार्ययोजनाओं को अंतिम रुप देने वाले जिलों की संख्या कितनी है और जिला निर्यात केंद्र (डीईएच)-अधिसूचित उत्पादों से दर्ज निर्यात की मात्रा का विषेषकर गाजियाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, राजमुंदरी और सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार, जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) डीईएच पहल के अंतर्गत कुल कितने उत्पाद-सेवा संकुलों की पहचान की गई है और उनके निर्यात प्रदर्शन मानक राज्यवार, जिलावार और वर्षवार क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्थानीय निर्यातकों को सहायता देने के लिए जिलों की संस्थागत और संभार तंत्र क्षमता का निर्माण करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिला निर्यात केन्द्र पहल के अंतर्गत पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए शुरु की गई क्षमता निर्माण पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार डीईएच पहल को ओएनडीसी, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस और इंडिया पोस्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख) और (ग) डीजीएफटी की निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत, जिलों से पहचाने गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिलों को सक्रिय हितधारक बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है ताकि उनकी वास्तविक प्रतिस्पर्धी

सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इस पहल ने कृषि, खिलौनों और जीआइ उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संपूर्ण देश के 734 जिलों में निर्यात क्षमता की पहचान की है।

आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा बाधाओं का विवरण देते हुए और उपरोक्त चिन्हित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित व्यवधानों की पहचान करते हुए 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार की गई है।

सरकार भारत से कुल निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। डीजीसीआईएस द्वारा राज्य-वार और जिले-वार निर्यात डेटा को मान्य नहीं किया गया है क्योंकि वे शिपिंग बिलों पर निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए अत्याधुनिक कोड पर आधारित हैं और जैसा कि सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त होता है। निर्यातकों द्वारा घोषित और सीमा शुल्क से प्राप्त राज्य-वार डेटा https://niryat.gov.in/ पर उपलब्ध है।

स्थानीय निर्यातकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर संस्थागत क्षमता और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. संस्थागत तंत्र को मजबूत करना: जिला-विशिष्ट निर्यात सुविधा पहलों की देखरेख करने, समस्याओं की समीक्षा करने और उचित मध्यस्थता की सिफारिश करने के लिए राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का संचालन और नियमित कार्यकरण।
2. डेटा प्रणालियों में सुधार: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, निर्यात रुझानों की अधिक गहनता से निगरानी और निर्यात क्षमता वाले उभरते क्षेत्रों की पहचान में सहायता के लिए निर्यात डेटा के जिला-स्तरीय कैप्चर को सक्षम करना।
3. लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति-श्रृंखला सुविधा: जिलों द्वारा पहचाने गए लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वेयरहाउसिंग, कोल्ड-चेन सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन बुनियादी संरचना और अन्य व्यापार से संबंधित सक्षमताओं में सुधार के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य एजेंसियों और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय।
4. उत्पाद-विशिष्ट मध्यस्थता पहचाने गए जिला उत्पादों या सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ गुणवत्ता वृद्धि, मानकीकरण, मूल्य-वर्धन और अनुपालन के लिए सहायता।

5. हितधारकों से संबंध: परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और व्यापार सुविधा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों, उद्योग संघों, एमएसएमई, कारीगरों के समूहों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ नियमित परामर्श।

(घ) डीईएच पहल के तहत पहली बार के निर्यातकों, कारीगरों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादक समूहों को सशक्त बनाने के लिए, राज्य सरकारों, व्यापार निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझेदारी में कई क्षमता-निर्माण और मार्गदर्शन गतिविधियां की गई हैं। इनमें शामिल हैं:

• निर्यात प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ीकरण, गुणवत्ता मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले आउटरीच और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम।

• पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल कैटलॉग की तैयारी, ई-कॉमर्स चैनलों के विपणन और उपयोग पर प्रशिक्षण मॉड्यूल।

• जिला चिन्हित उत्पादों से जुड़े कारीगरों, बुनकरों, कृषिगत समूहों, ग्रामीण सहकारी समितियों और सूक्ष्म उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल वृद्धि कार्यशालाएं।

• निर्यातकों को उत्पाद-वार निर्यात क्षमता, नियामक मानदंड, बाजार पहुंच के अवसर और व्यापार सुविधा स्कीम पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डीईएच के तहत विकसित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जिला स्तरीय सूचना प्रणाली के माध्यम से जानकारी का प्रसार।

• स्थानीय उत्पादक समूहों की प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजाइन क्षमताओं और बाजार अभिविन्यास में सुधार के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के साथ सहयोग।

(ड.) डीईएच पहल द्वारा बेहतर डिजिटल और लॉजिस्टिक्स संपर्क के माध्यम से जिला के पहचाने गए उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के अवसरों की खोज जारी है। डिजिटल वाणिज्य प्लेटफार्मों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और क्षेत्रीय सेवा प्लेटफार्मों के साथ जुड़ाव विपणन मार्गों को बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, व्यापक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ छोटे उत्पादकों के एकीकरण को बढ़ावा देता है और माल की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। निर्यातकों की बढ़ती आवश्यकताओं और जिलों को घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भागीदार संस्थानों के परामर्श से इस तरह के सहयोगी प्रयास किए जाते हैं।

* * * * *